Indian Journal of Commerce, Business & Management (IJCBM)
A Peer Reviewed Research journal of Commerce, Business & Management

ISSN : 3108-057X (Online)
3108-1282 (Print)
Vol.-2; Issue-1 (Jan.-March) 2026
Page No.- 57-64
©2026 **IJCBM**
https:// ijcbm.gyanvividha.com

Author's :

Ms Renu Bala Sharma

Research Scholar, Mahatma Jyoti Rao Phoole University, Jaipur.

Corresponding Author :

Ms Renu Bala Sharma

Research Scholar, Mahatma Jyoti Rao Phoole University, Jaipur.

राजस्थान स्टार्टअप-निर्यात (2015-2025) : रुझान और संरचना

सारांश : यह अध्ययन राजस्थान के निर्यात और स्टार्टअप-इकोसिस्टम के अंतर्संबंध को 2015-16 से 2024-25 तक के संदर्भ में मूल्य-आधारित विश्लेषण द्वारा समझाता है। राज्यवार निर्यात के लिए आधिकारिक स्रोतों, विशेषकर राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024, आर्थिक समीक्षा 2021-22, संसद प्रश्नोत्तर आधारित DGCI&S डेटा, और FIEO राज्य-प्रोफ़ाइल का उपयोग किया गया है। स्टार्टअप आयाम के लिए DPIIT फैक्टबुक, राजस्थान राज्य-रिपोर्ट, राज्य स्टार्टअप नीतियाँ, तथा iStart प्रोफ़ाइल-आधारित केस स्टडी उपयोग में ली गई हैं। अध्ययन पाता है कि राजस्थान का निर्यात आधार पारंपरिक उत्पाद-समूहों पर टिका है, लेकिन सेवाधारित और प्लेटफ़ॉर्म-आधारित स्टार्टअप निर्यात नई संरचना बना रहे हैं। फिर भी, 2024-25 के लिए क्षेत्र-वार सार्वजनिक आँकड़े अनुपलब्ध हैं और सेवा-निर्यात, विशेषकर IT/ITeS, वस्तु-निर्यात तालिकाओं में पूर्णतः परिलक्षित नहीं होते। इस कारण नीति-सिफारिशों का केंद्र डेटा-पारदर्शिता, प्रमाणन-संरचना, निर्यात-सज्ज स्टार्टअप पाइपलाइन, लॉजिस्टिक्स और बाज़ार-विविधीकरण पर रखा गया है।

कुंजीशब्द : राजस्थान, स्टार्टअप, निर्यात, डीजीसीआईएंडएस, डीजी-एफटी, आईटी/आईटीईएस, हस्तशिल्प, वस्त्र, औषधि, नीति विश्लेषण।

परिचय : राजस्थान का निर्यात-विकास अब केवल पारंपरिक व्यापार का प्रश्न नहीं रह गया है। राज्य सरकार की राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024 स्पष्ट रुप से स्वीकार करती है कि वित्त वर्ष 2023-24 में राज्य का कुल वस्तु-निर्यात ₹83,704.24 करोड़ रहा। इस निर्यात ढांचे का प्रमुख आधार इंजीनियरिंग सामग्री, रत्न-आभूषण, वस्त्र, धातु, हस्तशिल्प, कृषि-खाद्य उत्पाद और रसायन जैसे क्षेत्र हैं, जो कुल निर्यात का 70 प्रतिशत से अधिक हिस्सा रखते हैं। यही नीति वर्ष 2029 तक राज्य के निर्यात को ₹1.5 लाख करोड़ तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित

करती है (राजस्थान सरकार, 2024)। राजस्थान एक अंतर्देशीय राज्य होने के बावजूद इन क्लस्टर-आधारित क्षेत्रों में अपनी मजबूत उपस्थिति रखता है। राज्य की आर्थिक समीक्षा 2021-22 और नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 में राजस्थान को "लैंडलॉक्ड स्टेट्स" श्रेणी में उच्च प्रदर्शन करने वाला राज्य माना गया है (राजस्थान सरकार, 2022; PIB, 2020)।

इस पृष्ठभूमि में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उभरता है कि राजस्थान का स्टार्टअप-तंत्र केवल घरेलू नवाचार और स्थानीय उद्यमिता का ढांचा है या वह निर्यात-क्षमता का एक नया प्रस्थान-बिंदु भी बन सकता है। स्टार्टअप इंडिया अभियान के अंतर्गत 2015 में जारी राजस्थान स्टार्टअप नीति और 2022 में उसकी संशोधित रूपरेखा ने राज्य में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत किया है। आई-स्टार्ट (iStart) प्लेटफॉर्म के माध्यम से हजारों स्टार्टअप्स को मान्यता, इनक्यूबेशन, फंडिंग और मार्केटिंग सहायता उपलब्ध कराई गई है। DPIIT के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान स्टार्टअप रैंकिंग में निरंतर प्रगति कर रहा है तथा iStart पोर्टल पर पंजीकृत स्टार्टअप्स में आईटी/आईटीईएस, हस्तशिल्प ई-कॉमर्स, एग्री-टेक, न्यूट्रास्यूटिकल्स और निर्यात-सुविधा प्लेटफॉर्म्स जैसे क्षेत्र उभर रहे हैं (DPIIT, 2025; DPIIT, 2026; राजस्थान सरकार, 2022)। इन स्टार्टअप्स की गतिविधियाँ अब केवल घरेलू बाजार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि प्रत्यक्ष सेवा-निर्यात, डिजिटल मार्केटप्लेस के माध्यम से हस्तशिल्प उत्पादों का वैश्विक विपणन तथा निर्यात-सुविधा प्लेटफॉर्म्स के रूप में भी सामने आ रही हैं।

निर्यात विश्लेषण में एक मौलिक सावधानी यह रखनी चाहिए कि निर्यात को "मूल्य" के आधार पर पढ़ा जाए, न कि भौतिक "मात्रा" के आधार पर। संसद में प्रस्तुत आधिकारिक उत्तर के अनुसार विभिन्न वस्तुओं की माप की इकाइयाँ अलग-अलग होती हैं—कुछ टन में, कुछ संख्या में, कुछ वर्ग मीटर में—इसलिए उन्हें जोड़कर तुलनात्मक विश्लेषण संभव नहीं होता (भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, 2024)। इसी कारण यह अध्ययन पूर्णतः मूल्य-आधारित है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान वस्तु-निर्यात तालिकाएँ सेवाधारित स्टार्टअप निर्यात, विशेषकर आईटी/आईटीईएस, सॉफ्टवेयर सेवाओं तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को आंशिक रूप से ही पकड़ पाती हैं। इसलिए "स्टार्टअप-निर्यात" की अवधारणा को दो आयामों में समझना आवश्यक है—(1) प्रत्यक्ष वस्तु एवं सेवा निर्यात तथा (2) निर्यात-सुविधा प्लेटफॉर्म्स जो आपूर्तिकर्ताओं को वैश्विक खरीदारों से जोड़ते हैं।

यह शोध राजस्थान के स्टार्टअप-निर्यात (2015-2025) के रुझानों और संरचना का मूल्य-आधारित विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि पारंपरिक निर्यात क्लस्टरों के साथ-साथ स्टार्टअप-नेतृत्व वाले नवाचार किस प्रकार राज्य के निर्यात परिदृश्य को नया आयाम दे रहे हैं। द्वितीयक स्रोतों—राजस्थान निर्यात नीति 2024, आर्थिक समीक्षा 2021-22, DGCI&S राज्यवार डेटा, FIEO राज्य-प्रोफाइल, DPIIT फैक्टबुक, राजस्थान स्टार्टअप नीतियाँ तथा iStart स्टार्टअप प्रोफाइल्स—के आधार पर यह अध्ययन 2015-16 से 2024-25 तक की अवधि को कवर करता है। शोध यह भी दर्शाता है कि हालांकि राजस्थान का निर्यात अभी भी इंजीनियरिंग, रत्न-आभूषण और हस्तशिल्प जैसे पारंपरिक क्षेत्रों पर निर्भर है, लेकिन स्टार्टअप्स सेवा-निर्यात, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और मूल्य-वर्धित कृषि उत्पादों के क्षेत्र में नई संरचना तैयार कर रहे हैं।

वर्तमान वस्तुस्थिति में डेटा-पारदर्शिता, सेवा-निर्यात मापन, प्रमाणन अवसंरचना तथा बाजार-विविधीकरण की चुनौतियाँ प्रमुख हैं। यह शोध इन्हीं अंतरालों को उजागर करते हुए नीति-स्तरीय सिफारिशें प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। इस प्रकार यह अध्ययन राजस्थान के निर्यात और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्संबंध को समझने का एक तथ्यात्मक आधार प्रदान करता है तथा राज्य की निर्यात-तैयारी को और अधिक मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध हो सकता है।

साहित्य समीक्षा, पद्धति, डेटा स्रोत और मान्यताएँ : उप-राष्ट्रीय निर्यात तैयारी पर नीति आयोग का एक्सपोर्ट

प्रीपेरड्नस इंडेक्स एक उपयोगी विश्लेषणात्मक ढाँचा देता है, जो नीति, व्यवसायीय पारितंत्र, निर्यात पारितंत्र और प्रदर्शन के स्तंभों पर राज्यों को पढ़ता है (PIB, 2020). राजस्थान की निर्यात नीति 2024 ने इसी ढाँचे को आधार माना है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 राजस्थान को EPI 2020 में “लैन्ड्लाक्ड स्टेट्स” श्रेणी में उच्च प्रदर्शनकर्ता बताती है और 2020-21 के निर्यात क्षेत्रीय योगदानों का विस्तृत विवरण देती है (राजस्थान सरकार, 2022). स्टार्टअप पक्ष पर, हालिया शोध राजस्थान की प्रगति को स्वीकार करते हुए वित्त, मान्यता और गहराई के अंतरालों की ओर संकेत करता है (शर्मा एंव अन्य, 2025).

यह अध्ययन द्वितीयक स्रोतों के समेकित उपयोग पर आधारित है। निर्यात के लिए राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024, आर्थिक समीक्षा 2021-22, संसद प्रश्नोत्तर में प्रकाशित DGCI&S-आधारित राज्यवार डेटा, तथा FIEO की राज्य-प्रोफ़ाइल श्रृंखला को आधार बनाया गया। स्टार्टअप के लिए स्टार्टअप इंडिया फैक्टबुक 2025, राजस्थान राज्य-रिपोर्ट 2026, राजस्थान स्टार्टअप नीति 2015, राजस्थान स्टार्टअप नीति 2022, और आई-स्टार्ट स्टार्टअप प्रोफ़ाइलों का उपयोग किया गया। DGCI&S की MSME EXIM रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट होता है कि UDYAM-पंजीकृत MSME निर्यात का विश्लेषण DGFT IEC और DGCI&S एकीकरण पर आधारित है; इससे राज्य-स्तरीय निर्यात पठन की प्रशासनिक विश्वसनीयता बढ़ती है, यद्यपि यह सभी निर्यातों को नहीं पकड़ता (DGCI&S, 2024).

राजस्थान की नीति-परिवर्तन रेखा को निम्न समयरेखा में देखा जा सकता है। यह समयरेखा राज्य की निर्यात-उन्मुख स्टार्टअप क्षमता के क्रमिक संस्थानीकरण को दिखाती है।

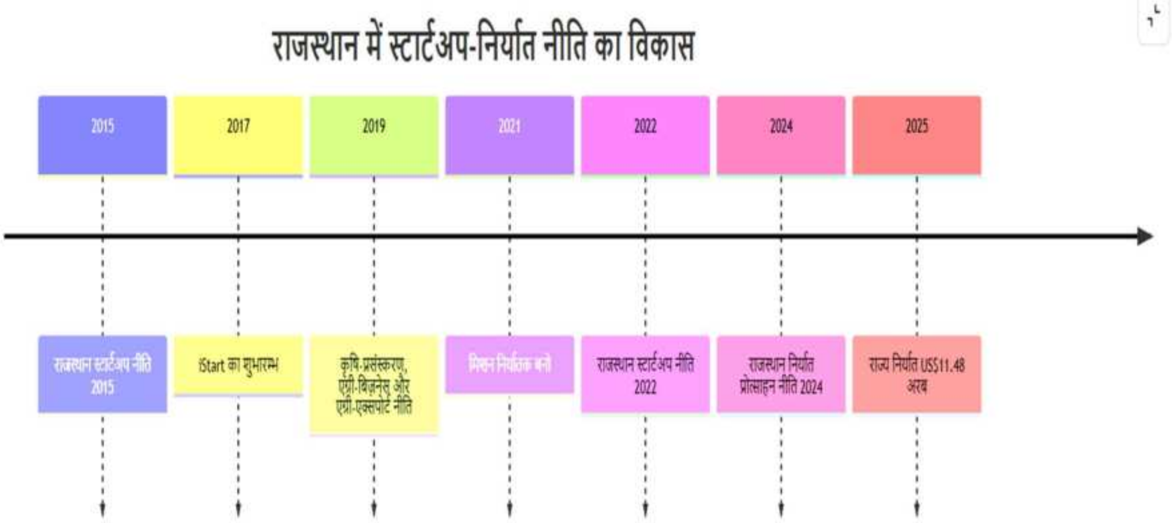

विश्लेषण और परिणाम : 2015-16 से 2023-24 के बीच राजस्थान का कुल वस्तु-निर्यात लगभग दोगुना हो गया है। संसद में प्रस्तुत DGCI&S आधारित आंकड़ों के अनुसार यह 2015-16 में US$5.24 अरब से बढ़कर 2023-24 में US$10.11 अरब हो गया। FIEO की 2024-25 राज्य-प्रोफाइल और DPIIT की राजस्थान राज्य रिपोर्ट के संकेतों से 2024-25 में कुल निर्यात US$11.48 अरब तक पहुँचने की संभावना है (वाणिज्य मंत्रालय, 2024; FIEO, 2025; DPIIT, 2026)। इस प्रकार पिछले दस वर्षों में निर्यात मूल्य में निरंतर वृद्धि स्पष्ट दिखाई दे रही है।

तालिका 1 में प्रस्तुत वार्षिक आंकड़े (₹ करोड़ में) इस प्रवृत्ति की पुष्टि करते हैं। 2015-16 में कुल निर्यात ₹36,047 करोड़ से 2023-24 में ₹83,704 करोड़ तक पहुँच गया। इस अवधि में इंजीनियरिंग, रत्न-आभूषण, वस्त्र,

हस्तशिल्प और कृषि-खाद्य उत्पादों जैसे पारंपरिक क्षेत्रों ने निर्यात वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया। हालांकि 2019-20 और 2020-21 में कोविड-19 महामारी के कारण थोड़ी गिरावट देखी गई, लेकिन 2021-22 से पुनः तेजी आई। 2022-23 में हस्तशिल्प श्रेणी में वर्गीकरण परिवर्तन के कारण अस्थायी गिरावट दर्ज हुई, जिसका उल्लेख राजस्थान निर्यात नीति 2024 में भी किया गया है (राजस्थान सरकार, 2024)।

2023-24 में निर्यात संरचना अभी भी इंजीनियरिंग, रत्न-आभूषण, वस्त्र, हस्तशिल्प और कृषि-खाद्य पर केंद्रित है, जो कुल निर्यात का 70 प्रतिशत से अधिक हिस्सा रखते हैं। हालांकि 2024-25 के लिए क्षेत्रीय विभाजन के विस्तृत सार्वजनिक आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। FIEO और राज्य रिपोर्ट कुल वृद्धि तो दर्शाती हैं, परंतु क्षेत्र-वार और उत्पाद-वार विस्तार अभी स्पष्ट नहीं है।

यह विश्लेषण दर्शाता है कि राजस्थान का निर्यात आधार मजबूत हो रहा है, लेकिन सेवा-निर्यात (विशेषकर आईटी/आईटीईएस) और स्टार्टअप-आधारित नई श्रेणियों का पूरा चित्र वर्तमान वस्तु-निर्यात डेटाबेस में अभी आंशिक रूप से ही उपलब्ध है। इसलिए कुल वृद्धि तो साफ है, परंतु क्षेत्रीय संरचना और स्टार्टअप-निर्यात की सटीक भूमिका को समझने के लिए अधिक पारदर्शी और विस्तृत डेटा की आवश्यकता है।

तालिका 1: राजस्थान के प्रमुख निर्यात क्षेत्रों का वार्षिक मूल्य, ₹ करोड़

वर्ष	इंजीनियरिंग	रत्न-आभूषण	वस्त्र	हस्तशिल्प	कृषि-खाद्य	औषधि	आईटी/ सॉफ़्टवेयर प्रॉक्सी	अन्य	कुल
2015-16*	4,976	5,035	4,647	3,387	3,289	415	2,157	12,141	36,047
2016-17	5,629	5,695	5,257	3,831	3,720	469	2,440	13,734	40,776
2017-18	7,350	5,264	5,667	3,702	4,205	605	2,531	17,153	46,477
2018-19	7,633	5,738	6,750	4,825	4,526	1,027	2,833	17,846	51,178
2019-20	7,675	5,110	6,166	5,219	3,709	1,900	2,730	17,437	49,946
2020-21	7,782	4,067	5,729	6,205	3,741	2,268	3,016	19,955	52,764
2021-22	11,966	6,811	9,251	7,830	5,180	2,578	465	27,918	72,000
2022-23	13,887	9,179	7,834	1,565	6,334	2,782	830	35,361	77,771
2023-24	16,593	11,183	8,820	7,987	6,487	2,954	1,110	28,571	83,704

**नोट: 2015-16 बैककास्टेड है। "अन्य" में धातु, रसायन, पत्थर, प्लास्टिक, कागज़, रबर आदि सम्मिलित हैं। 2022-23 में हस्तशिल्प का असामान्य गिराव संभवतः "clubbing under one head" प्रकृति से प्रभावित है, जैसा नीति-दस्तावेज़ के अस्वीकरण में कहा गया है (राजस्थान सरकार, 2024).*

2023-24 का उत्पाद-आधारित संकेंद्रण इंजीनियरिंग, रत्न-आभूषण, वस्त्र, हस्तशिल्प और कृषि-खाद्य पर टिका है। राज्य नीति 2024 इन्हें प्रमुख क्षेत्र बताती है और 2020-21 की आर्थिक समीक्षा भी इंजीनियरिंग, हस्तशिल्प, वस्त्र, धातु और रसायन को शीर्ष निर्यात-समूहों में रखती है। यह निरंतरता इस तर्क को मज़बूत करती है कि राजस्थान का निर्यात अभी भी "क्लस्टर-आधारित विनिर्माण + परंपरागत शिल्प" ढांचे से संचालित है, जबकि औषधि और डिजिटल/सॉफ्टवेयर अभी उभरते हुए घटक हैं (राजस्थान सरकार, 2022; राजस्थान सरकार, 2024).

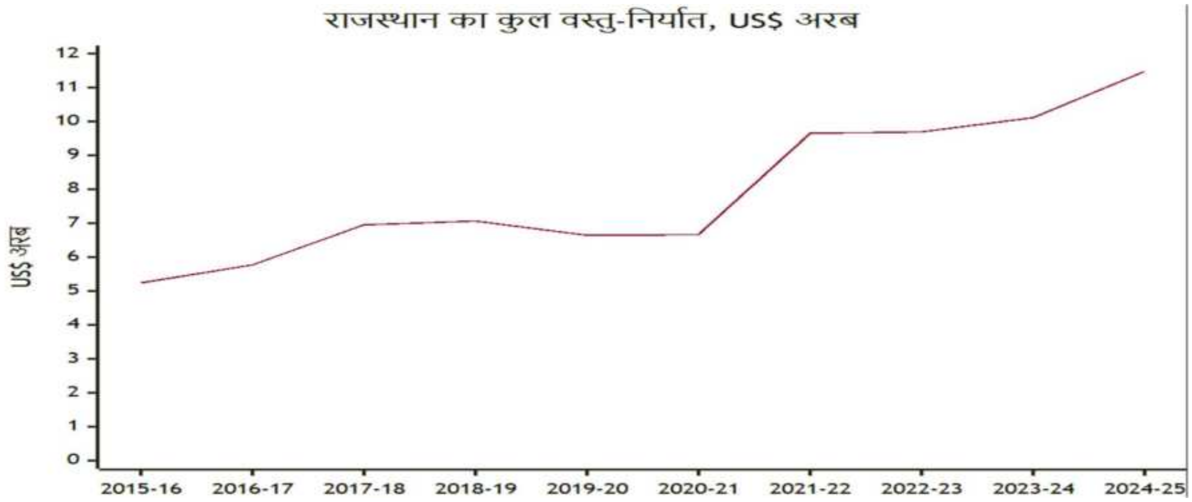

उपरोक्त प्रवृत्ति-रेखा की श्रृंखला संसद-आधारित DGCI&S राज्यवार डेटा, और 2024-25 के लिए FIEO/राज्य-रिपोर्ट पर आधारित है।

तालिका 2: 2023-24 में शीर्ष निर्यात गंतव्य

(नीति-चित्र में मान "हज़ार करोड़" पैमाने पर पढ़े जाने योग्य हैं)

गंतव्य	मूल्य	कुल में लगभग हिस्सा
संयुक्त राज्य अमेरिका	17.16	20.5%
संयुक्त अरब अमीरात	6.09	7.3%
यूनाइटेड किंगडम	3.21	3.8%
जर्मनी	2.84	3.4%
तुर्की	2.73	3.3%
बांग्लादेश	2.45	2.9%
सिंगापुर	2.42	2.9%
थाईलैंड	2.32	2.8%
हांगकांग	2.27	2.7%
जापान	2.26	2.7%

स्रोत: राजस्थान सरकार (2024). ये शीर्ष 10 गंतव्य मिलकर लगभग आधा निर्यात समेटते हैं, इसलिए बाज़ार-विविधीकरण नीति का प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है।

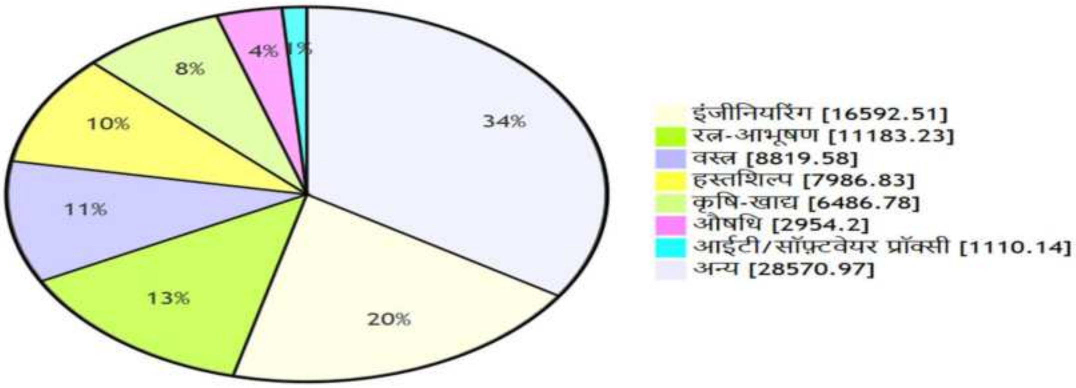

पाई-चार्ट के आँकड़े तालिका 1 के 2023-24 से पुनर्गठित किए गए हैं। "नवीकरणीय/क्लीन-टेक" का अलग निर्यात-शीर्षक राज्य की सार्वजनिक वस्तु-निर्यात तालिका में उपलब्ध नहीं है; इसलिए उसे "अन्य" के भीतर माना गया है।

तालिका 3: निर्यात-संबंधी गतिविधि वाले चुनिंदा राजस्थान स्टार्टअप

स्टार्टअप	क्षेत्र	निर्यात/वैश्विक गतिविधि का स्वरूप
West India Works	IT/ITeS	आईटी और आउटसोर्सिंग समाधानों का निर्यात; रिमोट-फ़र्स्ट वैश्विक सेवा मॉडल
Caradora Health Solutions Pvt. Ltd.	एग्री-न्यूट्रास्यूटिकल	स्पिरुलिना और अन्य algae-based supplements का "cultivate and export" मॉडल
Foothro	हस्तशिल्प-प्लेटफ़ॉर्म	भारतीय कला, शिल्प और हस्तनिर्मित उत्पादों का वैश्विक डिजिटल मार्केटप्लेस
Shrrida Vyapar Vraddhi Pvt. Ltd.	निर्यात-सुविधा	भारतीय आपूर्तिकर्ताओं को अंतरराष्ट्रीय खरीदारों से जोड़ने वाला "Export Easy" प्लेटफ़ॉर्म
9 Planet Impex	कृषि/उपभोक्ता व्यापार	मसाले, अनाज, तेल, ड्राइ-फ्रूट आदि का बहु-उत्पाद import-export मॉडल
Interverse Foods Pvt. Ltd.	कृषि-उत्पाद	कृषि उत्पादों के निर्यात और अंतरराष्ट्रीय डिलीवरी में सक्रिय

ये केस यह दिखाते हैं कि राजस्थान में स्टार्टअप-निर्यात केवल वस्तु-उत्पादन तक सीमित नहीं है; इसमें सेवा-निर्यात, शिल्प-आधारित ई-कॉमर्स, एग्री-न्यूट्रास्यूटिकल, और निर्यात-सुविधा प्लेटफ़ॉर्म भी शामिल हैं।

चर्चा, तुलनात्मक बेंचमार्क और नीतिगत सिफारिशें : राष्ट्रीय तुलना में राजस्थान अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन करता दिखता है। 2015-16 से 2023-24 के बीच राजस्थान का वस्तु-निर्यात US$5.24 अरब से US$10.11 अरब हुआ, जबकि भारत का कुल वस्तु-निर्यात US$262.29 अरब से US$437.11 अरब हुआ। लेखक की गणना के अनुसार राजस्थान का CAGR लगभग 8.6 प्रतिशत और भारत का लगभग 6.6 प्रतिशत है। 2023-24 में राजस्थान का राष्ट्रीय वस्तु-निर्यात में हिस्सा लगभग 2.31 प्रतिशत था; FIEO के अनुसार 2024-25 में यह 2.6 प्रतिशत तक पहुँचा। इसका अर्थ यह नहीं कि राजस्थान शीर्ष-स्तरीय निर्यात राज्य बन चुका है, बल्कि यह कि उसने अपेक्षाकृत तेज़ वृद्धि दर्ज की है (वाणिज्य मंत्रालय, 2024; FIEO, 2025).

स्टार्टअप पारितंत्र के दृष्टिकोण से राजस्थान की सबसे बड़ी ताकत उसका संस्थागत ढाँचा है। 2015 नीति ने ससटेनेंस अलाउन्स , मार्केटिंग असिस्टेंस और इनक्यूबेटोर ग्रांटस जैसे आधारभूत उपकरण दिए; 2022 नीति ने इन्हें विस्तारित किया; 2026 राज्य-रिपोर्ट आईडीएशन ग्रांट, स्केल-अप फंड, स्टार्टअप एक्विटी फंड और प्रोक्योरमेंट रीलैक्सैशन का अधिक विकसित सेट दिखाती है। फिर भी दो महत्वपूर्ण सीमाएँ बनी हुई हैं। पहली, DPIIT-मान्यता, राज्य-पोर्टल पंजीकरण और वास्तविक जीवित स्टार्टअपों की गणना अलग-अलग संख्याएँ देती है, इसलिए स्टार्टअप-घनत्व का कोई एकल आँकड़ा भ्रामक हो सकता है। दूसरी, IT/ITeS और निर्यात-सुविधा सेवाओं का बड़ा हिस्सा वस्तु-निर्यात डेटाबेस में नहीं दिखता, इसलिए "स्टार्टअप निर्यात" का वास्तविक आकार प्रकाशित तालिकाओं से अधिक हो सकता है (DPIIT, 2025; DPIIT, 2026; Startup India, 2015).

नीति के स्तर पर पाँच सिफारिशें निकलती हैं। पहली, डीजीएफटी और वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय आधारित राज्य-उद्गम निर्यात डेटाबेस का वार्षिक, मशीन-पठनीय प्रकाशन हो, ताकि 2022-23 जैसे

वर्गीकरण-विस्थापन की व्याख्या हो सके। दूसरी, iStart और निर्यात नीति को जोड़कर "एक्सपोर्ट रेडी स्टार्टअप ट्रैक" बनाया जाए, जिसमें IEC, RCMC, गुणवत्ता-प्रमाणीकरण, परीक्षण और अंतरराष्ट्रीय बाज़ार-प्रवेश के लिए एकीकृत परामर्श हो। तीसरी, परीक्षण और अनुपालन लागत घटाने के लिए साझा लैब, पैकेजिंग सहायता और प्रमाणन-वाउचर व्यवस्था विकसित की जाए; राज्य नीति पहले ही 50 प्रतिशत दस्तावेज़ी/प्रमाणीकरण सहायता और 75 प्रतिशत उत्पाद-परीक्षण प्रतिपूर्ति जैसी धाराएँ रखती है। चौथी, अमेरिका और UAE पर उच्च निर्भरता को देखते हुए बाज़ार-विविधीकरण कार्यक्रमों को तेज़ किया जाए। पाँचवीं, क्लीन-टेक और नवीकरणीय-ऊर्जा स्टार्टअपों को निर्यात-सक्षम आपूर्ति-श्रृंखलाओं से जोड़ा जाए, क्योंकि नीति-स्तर पर ऐसे क्षेत्र समर्थित हैं पर सार्वजनिक निर्यात-डेटा में पृथक नहीं दिखते (राजस्थान सरकार, 2024; DPIIT, 2026).

निष्कर्ष : इस अध्ययन से तीन प्रमुख निष्कर्ष उभरकर सामने आते हैं।

पहला, राजस्थान का निर्यात आधार वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक न केवल आकार में बल्कि विविधता के स्तर पर भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। इस अवधि में राज्य का वस्तु-निर्यात लगभग दोगुना हो गया है, जो निरंतर नीतिगत प्रयासों और बाजार अनुकूलन की सफलता को दर्शाता है। DGCI&S, FIEO तथा राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024 के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि कुल निर्यात US$5.24 अरब से बढ़कर US$11.48 अरब तक पहुंच गया है।

दूसरा, निर्यात वृद्धि का मुख्य भार अभी भी पारंपरिक क्षेत्रों; इंजीनियरिंग, रत्न-आभूषण, वस्त्र, हस्तशिल्प तथा कृषि-खाद्य उत्पादों पर ही है। ये क्षेत्र कुल निर्यात का 70 प्रतिशत से अधिक योगदान देते हैं। वहीं, स्टार्टअप-नेतृत्व वाला निर्यात मुख्य रूप से IT/ITeS सेवाओं, हस्तशिल्प ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, एग्री-न्यूट्रास्यूटिकल्स और निर्यात-सुविधा प्लेटफॉर्म्स के क्षेत्र में तेजी से उभर रहा है। यह दर्शाता है कि स्टार्टअप्स राज्य के निर्यात परिदृश्य में नई संरचना और मूल्य-वर्धन का योगदान दे रहे हैं।

तीसरा, राजस्थान सरकार ने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए 2015 और 2022 की स्टार्टअप नीतियों के माध्यम से एक मजबूत संस्थागत ढांचा विकसित कर लिया है। फिर भी, डेटा-पारदर्शिता, प्रमाणन अवसंरचना, सेवा-निर्यात का सटीक मापन और गुणवत्ता परीक्षण सुविधाओं जैसी कुछ महत्वपूर्ण कमजोरियाँ अभी भी बनी हुई हैं।

इन निष्कर्षों के आधार पर कहा जा सकता है कि राजस्थान की निर्यात नीति का अगला चरण मात्र लक्ष्य-घोषणा तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसके बजाय इसे "डेटा-आधारित निर्यात-तैयारी" (Data-driven Export Preparedness) की दिशा में ले जाना होगा। डेटा पारदर्शिता बढ़ाना, स्टार्टअप्स को निर्यात-तैयार बनाने के लिए एकीकृत ट्रैक विकसित करना और बाजार विविधीकरण पर ध्यान केंद्रित करना राज्य को अपने निर्यात लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा।

यह अध्ययन स्पष्ट करता है कि यदि पारंपरिक क्लस्टरों की मजबूती को स्टार्टअप नवाचार के साथ जोड़ा जाए तो राजस्थान भविष्य में एक अधिक प्रतिस्पर्धी और विविध निर्यातक राज्य के रूप में उभर सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. **राजस्थान सरकार.** (2024). राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024. आईस्टार्ट राजस्थान. https://istart.rajasthan.gov.in/public/Policies/2024/rajasthan-export-promotion-policy-2024.pdf
2. **राजस्थान सरकार.** (2022). आर्थिक समीक्षा 2021-22. वित्त विभाग. https://finance.rajasthan.gov.in/docs/budget/statebudget/2022-2023/EconomicReviewE.pdf

3. **भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय.** (2024). लोकसभा अनतारांकित प्रश्न संख्या 2416: राज्य-वार निर्यात आंकड़े. https://www.commerce.gov.in/wp-content/uploads/2024/08/LS-USQ-No.2416-dt.-06.08.2024.pdf
4. **भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय.** (2025). वार्षिक रिपोर्ट 2024-25. https://www.commerce.gov.in/ministryofcommerce/sites/default/files/2025-08/Commerce_AR-2024-25-English-1.pdf
5. **उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी).** (2025). स्टार्टअप इंडिया नौ वर्षीय तथ्य पुस्तिका. https://www.startupindia.gov.in/content/dam/invest-india/startup-milestone/FactbookJan25.pdf
6. **उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी).** (2026). राज्यों का स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र रैंकिंग: राजस्थान राज्य रिपोर्ट. https://www.startupindia.gov.in/srf/portal/SRF_2026_Result_page/Rajasthan_State_Report.pdf
7. **स्टार्टअप इंडिया.** (2015). राजस्थान स्टार्टअप नीति 2015. https://www.startupindia.gov.in/content/dam/invest-india/Templates/public/state_startup_policies/Rajasthan-startup-policy-2015.pdf
8. **राजस्थान सरकार.** (2022). राजस्थान स्टार्टअप नीति 2022. https://istart.rajasthan.gov.in/public/pdf/Rajasthan_Startup_Policy_2022.pdf
9. **भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्सिम बैंक).** (2016). राजस्थान से निर्यात को बढ़ावा देना. https://www.eximbankindia.in/sites/default/files/2025-07/Rajasthan.pdf
10. **वाणिज्यिक खुफिया एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस).** (2024). भारत के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र का माल निर्यात-आयात स्थिति रिपोर्ट, 2022-23. https://dgciskol.gov.in/writereaddata/Downloads/20240108161432MSME%20SECTOR%20EXIM%20REPORT%202022-23.pdf
11. **प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी).** (2020). नीति आयोग ने निर्यात तैयारिता सूचकांक 2020 पर रिपोर्ट जारी की. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1648679
12. **भारतीय निर्यात संगठनों का महासंघ (एफआईईओ).** (2025). राज्यों के निर्यात का अवलोकन 2024-25. https://fieo.org/view_section.php?id=0%2C2111%2C2883&lang=0
13. **शर्मा, डी., एवं अन्य.** (2025). राजस्थान में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र: भारत के उच्च-प्रदर्शन वाले राज्यों के साथ तुलनात्मक विश्लेषण. https://www.managementjournals.net/assets/archives/2025/vol7issue1/7017.pdf
14. **आईस्टार्ट राजस्थान.** (2026). स्टार्टअप प्रोफाइल पृष्ठ एवं स्टार्टअप सूची. https://istart.rajasthan.gov.in/startup-list
15. **वेस्ट इंडिया वर्क्स.** (2026). कंपनी प्रोफाइल. https://istart.rajasthan.gov.in/profile/3793/startups

•